Indian Journal of
Social Sciences Research and Analytics
Website: www.thearyapublication.com

Research Article
IJSSRA | ……………………
April-June 2025 | Vol 01 Issue 1

भारतीय परीक्षा प्रणाली में मूल्यांकन एवं रचनावाद

विवेक जैसवार*

***शोधार्थी, शिक्षा विभाग, बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ , उत्तर-प्रदेश, भारत.**
ई-मेल: bbauv25@gmail.com

DOI: doi.org/10.5281/zenodo.15613752
Received on: 10/04/2025, Revised on: 12/05/2025, Accepted on: 20/05/2025, Published on: 10/06/2025

सारांशिका :

भारतीय शिक्षा प्रणाली को मुख्यतः तीन स्तरों में विभाजित किया गया है- प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च स्तरीय शिक्षा। शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर परीक्षा का आयोजन ज्यादातर वर्ष के अंत में किए जाते है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के फलस्वरूप शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर विद्यार्थियों का शैक्षिक मूल्यांकन वर्ष में कई बार होने लगे है जिससे शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया में नवीन सुधार हुआ है। नई शिक्षा नीति में विद्यार्थियों की शैक्षिक सुधार के लिए पाठ्यक्रम में लचीलापन तथा गतिविधि आधारित शिक्षा देने की सिफारिश की गई है जो कि रचनावाद शिक्षा की देन है। रचनावादी शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों के मूल्यांकन की संरचना इस प्रकार से की जाती है कि विद्यार्थी स्व-आकलन तथा साथी समूह के साथ सीखते हुए अपने अधिगम प्रतिफल को सार्थक बनाते रहते है। वर्तमान परीक्षा प्रणाली में वर्ष के अंत में विद्यार्थियों को परीक्षा फल के रूप में प्रमाण-पत्र देने की प्रक्रिया विद्यमान है जिससे विद्यार्थियों के अन्दर सीखने का उद्देश्य सिर्फ प्रमाण पत्र प्राप्त करना रह जाता है। प्रचलित परीक्षा प्रणाली का मूल्यांकन रचानावादी शिक्षा के अनुसार करने से विद्यार्थियों के अन्दर उचित कौशलों का विकास होता है। प्रस्तुत शोध आर्टिकल में यह बताने का प्रयास किया गया है कि रचनावादी शिक्षा के द्वारा मूल्यांकन करने से विद्यार्थियों का अधिगम प्रतिफल अधिक सार्थक होता है।

मुख्य शब्द: मूल्यांकन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, रचनावाद।

प्रस्तावना:

भारतीय शिक्षा प्रणाली में वर्ष के अंत में परीक्षा का आयोजन प्राचीन समय से होता रहा है। परम्परागत परीक्षा प्रणाली में परीक्षा का आयोजन मौखिक रूप से होता था शिक्षक मौखिक रूप से छात्रो से प्रश्न पूछते थे और छात्र रटे रटाये ज्ञान के अनुसार उत्तर देते थे। विद्यार्थियों के उत्तर के अनुसार उनका मूल्यांकन होता था। कुछ समय पश्चात् विद्यार्थियों का

मूल्यांकन लिखित परीक्षा के माध्यम से होने लगा। स्वतंत्रता के बाद विश्वविद्यालय आयोग का गठन के फलस्वरूप स्नातक स्तर की परीक्षा प्रणाली में बदलाव किया गया तथा परीक्षा में लिखित और मौखिक परीक्षा का आयोजन होने लगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के क्रियान्वयन के बाद शिक्षा के प्रत्येक स्तर के परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन किया गया। इस नीति का समय-समय पर संशोधन भी किया जाता रहा। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में प्रथम बार 'परीक्षा प्रक्रिया के इन कमियों को दूर करके इसे अधिक प्रभावशाली तथा सार्थक बनाने के लिए सेमेस्टर परिक्षा प्रणाली के आयोजन का सुझाव दिया गया' (गुप्ता,2011)। और परीक्षा के मूल्यांकन के लिए ग्रेडिंग पद्धति को अपनाने का सुझाव दिया गया। धीरे-धीरे विश्वविद्यालयी स्तर की परीक्षा में इसे लागू कर दिया गया। इस प्रणाली में परीक्षा के प्रश्न में भी बदलाव आया परीक्षा लिखित एवं मौखिक होने लगी तब से लेकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के पहले तक इसी अनुसार परीक्षा का आयोजन होता रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के बाद परीक्षाओं के आयोजन में सतत आकलन करते हुए मूल्यांकन करने पर बल दिया जा रहा इस नीति में प्रथमिक स्तर की परीक्षा में तत्काल परिवर्तन किया गया तथा प्राथमिक स्तर पर सत्रीय, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षाओ का आयोजन होने लगा जिसका आधार रचनावाद है क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में रचनावाद शिक्षा प्रणाली का प्रभाव है।

वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में मूल्यांकन:

वैदिक काल में गुरुकुलो में परीक्षा विहीन प्रणाली की व्यवस्था थी। गुरु नए पाठ का आरंभ तभी करता था जब विद्यार्थियों को पुराने पाठ कंठस्थ हो जाते थे। गुरु अपने शिष्यों को समूहों में विभक्त करके शास्त्रार्थ कराते थे और प्रत्येक विद्यार्थी को शास्त्रार्थ के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ता था। शास्त्रार्थ के अनुसार गुरु अपने शिष्यों का मूल्यांकन करता रहता था। 'वैदिक समय में शिक्षा व्यवस्था विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित होती थी तथा इसी अनुसार विद्यार्थियों को श्रवण ,मनन तथा चिंतन कराया जाता था'(पाण्डेय, 2011)।

बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में मूल्यांकन:

बौद्ध काल को शिक्षा का स्वर्ण युग कहा जाता था क्योंकि इस समय भारत में कई विश्वविद्यालयों कि स्थापना की गई। नालंदा विश्वविद्यालयों में सबसे प्रमुख था। इस काल में वियार्थियों का शैक्षिक मूल्यांकन उनकी निपुणता पर निर्भर करता था। विद्यार्थियों को पूर्णतया निपुण हो जाने के बाद ही उसे अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाता था।

मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली में मूल्यांकन: मध्य कालीन समय में परीक्षाओं का आयोजन आधुनिक युग की समान नहीं होता था। शिक्षक अपने समझ और विवेक के अनुसार विद्यार्थियों को एक कक्षा से अगली कक्षा में प्रोन्नति करते रहते थे।

एक कक्षा से अगली कक्षा में प्रवेश के लिए कोई निश्चित मानदंड नहीं होता था और न ही कोई निश्चित समयावधि निर्धारित रहती थी। “शिक्षा समाप्ति के बाद प्रमाण पत्र वितरण का प्रचलन नहीं था लेकिन विशेष योग्यता के आधार पर काबिल, फाजिल एवं आलिम आदि की उपाधियाँ दी जाती थी” (पाण्डेय, 2011)।

स्वतंत्र भारत की शिक्षा प्रणाली में मूल्यांकन:

15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ इसके तुरंत बाद ही 1948 में राधा कृष्णन आयोग का गठन हुआ, इस आयोग ने परीक्षा प्रणाली में सुधार की बात कही तथा यह सुझाव दिया की परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों के वर्ष भर के कार्यों का मूल्यांकन होना चाहिए। चूकि इस आयोग को विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है अतः इसने ज्यादातर उच्च शिक्षा के बारे में अपने सुझाव प्रस्तुत किए। इस आयोग ने कहा की स्नातक की परीक्षा प्रत्येक वर्ष आयोजित किए जाए। वार्षिक परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ तथा मौखिक प्रश्नों को स्थान देने का सुझाव दिया। इस आयोग का प्रभाव वर्तमान परीक्षा प्रणाली पर आज भी परिलक्षित होता है, वर्तमान स्नातक की परीक्षा प्रणाली में भी वर्ष के अंत में परीक्षाओ का आयोजन किया जाता है तथा प्रमाण पत्र दिए जाने की व्यवस्था प्रचलित है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में मूल्यांकन:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति,1986 में परीक्षा प्रणाली के मूल्यांकन पर विशेष बल दिया गया। विश्वविद्यालय आयोग के सिफारिशे के अनुरूप कार्य किया गया। स्नातक स्तर पर प्रति वर्ष परीक्षाओ का आयोजन विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए होने लगा तथा 10+2+3 शिक्षण सूत्र का प्रयोग होने लगा। इस नीति में मूल्यांकन व्यवस्था में सुधार करते हुए विद्यार्थियों का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करते हुए परीक्षाओं में सेमेस्टर एवं ग्रेडिंग प्रणाली लागू किया। इस शिक्षा नीति में जवाहर नयोदय विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थियों का एडमिशन प्रवेश परीक्षा के माध्यम से कराने की योजना बनाई। तभी से लेकर आज तक परीक्षा प्रणाली का मूल्यांकन इसी के अनुरूप किया जाता रहा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मूल्यांकन:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जिसे नई शिक्षा नीति भी कहा जाता है। इस नीति में शिक्षा संरचना 10+2+3 से बदलकर 5+3+3+4 कर दिया गया। इस नीति में सतत एवं आतंरिक मूल्यांकन पर विशेष बल दिया गया तथा तथा प्रारंभिक स्तर की शिक्षा में इसका क्रियान्वयन भी किया जाने लगा। इस नीति ने प्रारंभिक स्तर की शिक्षा में बुनियादी शिक्षा एवं साक्षरता ज्ञान के अंतर्गत विद्यार्थियों का प्रत्येक सप्ताह आकलन किया जा रहा तथा सत्र परीक्षा अर्थात तिमाही, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा जिससे वर्ष भर विद्यार्थियों के प्रत्येक पहलूओं का आकलन करते हुए

मूल्यांकन कार्य संपन्न हो रहा जिससे विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि में उत्तरोत्तर वृद्धि तथा जीवन कौशलों का विकास हो रहा। कोरोना काल में माध्यमिक स्तर की परीक्षा के मूल्यांकन में कक्षा 10 एवं कक्षा 12 के विद्याथियों के लिए प्री बोर्ड की परीक्षा प्रणाली का आयोजन किया गया इस परीक्षा के आयोजन से परीक्षार्थियों में बोर्ड परीक्षा का भय अपेक्षाकृत कम हुआ। तब से माध्यमिक स्तर की परीक्षा में अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड तथा वार्षिक परीक्षा का आयोजन विद्याथियों के मूल्यांकन कार्य के लिए होने लगा। उच्च शिक्षा के परीक्षा प्रणाली में सेमेस्टर आधारित परीक्षा का आयोजन किया जा रहा तथा ग्रेडिंग पद्धति के माध्यम से विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जा रहा। इस नीति में विद्यार्थियों की सह पाठ्यक्रम गतिविधि का आकलन करते हुए मूल्यांकन करने पर बल दिया जा रहा। परीक्षा में प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ तथा खुले प्रकार के बनाये जाने पर विशेष बल दिया जा रहा।

रचनावाद:

रचनावाद का अर्थ– अधिगमकर्ता द्वारा आपने अनुभवों तथा पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान का सृजन करना ही रचनावाद है "रचनावाद ज्ञान और सीखने के बारे में एक सिद्धांत है जो यह बताता है कि जानना क्या है और व्यक्ति को इसके बारे में पता चलता रहता है"(फास्नाट, 1996) इस अधिगम प्रणाली में शिक्षक का स्थान एक कुशल सुविधा प्रदाता के रूप में होता है। शिक्षक अपने विवेक के अनुसार विद्यार्थियों के लिए प्रश्न पत्र का निर्माण प्रत्येक पाठ के लिए स्वयं करता है और उसके प्रत्येक पहलुओं का आकलन करते हुए मूल्यांकन करता रहता है। रचनावाद शिक्षण प्रणाली में मूल्यांकन: इस आधिगम प्रणाली में रोजर्स बाईबी (1997) द्वारा दिया गया 5ई अधिगम प्रतिमान का प्रयोग वर्तमान परीक्षा प्रणाली में प्रयोग करने से विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि को बढ़ाया जा सकता है। 5 ई का अधिगम चक्र में अधिगम का कार्य पांच चक्रों में चलता है– एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलाबोरेट और एवैलुएट। 5ई प्रतिमान के अंतिम सोपान एवैलुएट है जिसका अर्थ मूल्यांकन है अर्थात विद्यार्थियों का सम्बंधित पाठ के समाप्ति पर मूल्यांकन करना होता है।इस प्रकार शिक्षक जो भी कार्य करता है उसका मूल्यांकन करता रहता है। और विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि में सुधार होता है। इस शिक्षण विधि में यह प्रक्रिया वर्ष भर चलती रहती है और विद्यार्थियों की अधिगम कमजोरियों का शिक्षक द्वारा उपचारित किया जाता है, परिणाम-स्वरूप विद्यार्थी परीक्षा के भय से भयमुक्त होकर परीक्षा देता है और अच्छे अंक प्राप्त कर लेता है।

निष्कर्ष:

निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि भारतीय परीक्षा प्रणाली में प्राचीन काल से वर्तमान समय तक क्रमशः बदलाव होते रहे है। पहले की परीक्षा प्रणाली ज्यादातर शिक्षक केन्द्रित होती थी, विद्यार्थियों के ऊपर अधिक पाठ्यक्रम का भार भी

रहता था। नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन तथा परीक्षा प्रणाली में रचनावाद के प्रयोग से विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि में निश्चय ही वृद्धि होगीं। रचनावाद शिक्षा प्रणाली में परीक्षा विद्यार्थी केन्द्रित होती है। नई शिक्षा नीति का आधार अधिकतर रचनावाद से उद्धृत है अतः शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक रचनावाद शिक्षण अधिगम प्रणाली का प्रयोग किया जाए जिससे विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि को सुधार कर भय मुक्त परीक्षा के वातावरण का सृजन संभव हो सके।

सन्दर्भ:

- गुप्ता, एस.पी. एंड गुप्ता, अल्का (2011). आधुनिक मापन एवं मूल्यांकन, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद।
- झा, ए. के. (2009). कंस्ट्रक्टिविस्ट एपिस्टोमेलोजी एंड पेडागॉजी: इनसाइट इंटू टीचिंग लर्निंग एंड नोइंग. अटलांटिक पब्लिशर एंड डिस्ट्रीब्यूटर, न्यू दिल्ली।
- पाण्डेय, रामशकल एवं जोशी, चन्द्रावती (2011). भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास. अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा।
- फास्नाट, सी.टी. (1996). कांसट्रक्टीविज्म: अ साइकोलाजिकल थ्योरी ऑफ़ लर्निंग. फास्नाट (ए.डी.), कांसट्रक्टीविज्मः थ्योरी, पर्सपेक्टिव्स एंड प्रैक्टिस, टीचर कॉलेज प्रेस, न्यूयार्क।
- फिलिप्स , डी. सी. (1995). द गुड, द बैड एंड द अग्ली: द मेनी फेसेस ऑफ़ कांसट्रक्टीविज्म. एजुकेशनल रीसर्च, (24), 5-12.
- बाईबी, आर. डब्ल्यू. (1997). अचिविंग साइंटिफिक लिटरेसी: फ्राम पर्पजेज टू प्रैक्टिसेज. पोर्ट्समाउथ, हेनमेन पब्लिशिंग, न्यू हेम्पशायर.
- मोहपत्र, जे. के., महापत्र, एम. एंड परिदा, बी. के. (2015). कंस्ट्रक्टिविज्म: द न्यू पैराडायम फ्रॉम थ्योरी एंड प्रैक्टिस, अटलांटिक पब्लिशर एंड डिस्ट्रीब्यूटर, न्यू दिल्ली।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020), शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

How to cite this paper:

जैसवार, वि. (2025). भारतीय परीक्षा प्रणाली में मूल्यांकन एवं रचनावाद. *इंडियन जर्नल ऑफ सोशल साइंसेज रिसर्च एंड एनालिटिक्स, 01*(1), 37-41. **doi.org/10.5281/zenodo.15613752**

Copyright: © the author(s). Published by the Arya Publication Services. This is an open-access article under the CC-BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).